प्रगति प्रपत्र

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग

विभागीय योजनाएँ

1. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 4–5
2. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 6
3. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017 7–10
4. उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति 2020 11
5. प्रस्तावित उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 12–13
6. शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली 14–15
7. राइट–ऑफ–वे पॉलिसी की ऑनलाइन व्यवस्था 16
8. नेशनल ब्रॉडबैण्ड मिशनः भारत नेट 17
9. जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी–3.0)/ई–डिस्ट्रिक्ट योजना 18
10. यूपी स्वॉन 2.0 19
11. उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर 20
12. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) योजना (जनसुनवाई पोर्टल) 21
13. उत्तर प्रदेश सेन्टर ऑफ जियो–इन्फॉर्मेटिक्स (यूपी सीओजी) 22
14. डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) 23
15. डिजिटल पेमेंट/डिजी लॉकर 24
16. उमंग/UMANG (Unified Mobile Application for New-Age Governance) 25

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017

उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017 के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र भारत के इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में हुए प्रतिष्ठित

- ✓ रू. 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य 3 वर्ष में ही प्राप्त
- ✓ 30 निवेशकों द्वारा प्रदेश में कार्य प्रारंभ
- ✓ लगभग 3,00,000 से अधिक रोजगार सृजन
- ✓ ग्रेटर नोएडा के 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) निर्माणाधीन

◆ वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात दिसम्बर 2017 में घोषित ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017'' में प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया था।

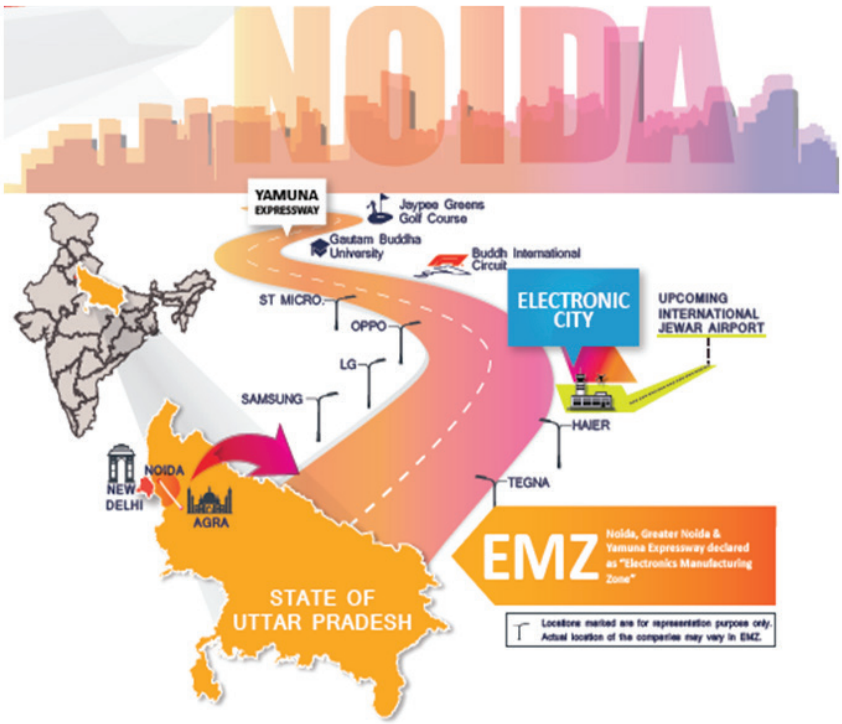

Project Location

2,840 Acres
Electronics City

Delhi | 40 km
Capital of India

165 Km Six Lane Yamuna Expressway

302Km Agra - Lucknow Expressway

57% of Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC)

15% of Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC)

◆ इस नीति के अन्तर्गत 5 वर्षों में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में रू0 20,000 करोड़ का निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नीति के अन्तर्गत रू0 20,000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही लगभग 30 निवेशको द्वारा प्रदेश में निवेश प्राप्त कर अर्जित कर लिया गया है तथा लगभग 3,00,000 से अधिक रोजगार सृजित हुये।

◆ ग्रेटर नोएडा के 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) निर्माणाधीन

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020

प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के समान विकास के साथ नीति संकल्पित

- ✓ उ. प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 में अगले 5 वर्षों में रु 40,000 करोड़ का निवेश और 4,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य
- ✓ ई.एस.डी.एम. उद्योग के प्रोत्साहन हेतु राज्य में 3 सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजन की योजना
- ✓ उत्पाद आधारित ली–आयन सेल हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (सी.ओ.ई.) की स्थापना को राज्य सरकार एवं भारत सरकार ने दिया सैद्धांतिक अनुमोदन
- ✓ जेवर के नजदीक इलेक्ट्रानिक सिटी की परिकल्पना
- ✓ बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ–उन्नाव–कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति 2017

◆ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग रू 200 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार की सम्भावनाओं से युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना भारत सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया (एस.टी.पी.आई.) के सहयोग से की जा रही है। मेरठ, आगरा, गोरखपुर एवं वाराणसी में आगामी वर्ष में इन आईटी पार्कों में संचालन प्रारम्भ होना सम्भावित है।

@ Agra IT Park

@ IT City, Lucknow

@ Meerut IT Park

उत्तर प्रदेश

◆ लखनऊ में 40 एकड़ भूमि पीपीपी मॉडल पर 'अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी काम्प्लेक्स' के अन्तर्गत एक आईटी पार्क और 4 एकड़ भूमि पर एस.टी.पी.आई. द्वारा देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेशन सेन्टर बनाये जाने की योजना है।

◆ इसके अतिरिक्त कानपुर, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ तथा झांसी में भी आईटी पार्कों के विकास हेतु कार्यवाही की जा रही है।

◆ राज्य सरकार की पहल के फलस्वरूप प्रदेश में आईआईएम लखनऊ, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एमिटी विश्वविद्यालय, केआईईटी गाजियाबाद जैसे प्रदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में 18 इन्क्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन के उपरान्त प्रारम्भ हो गये हैं।

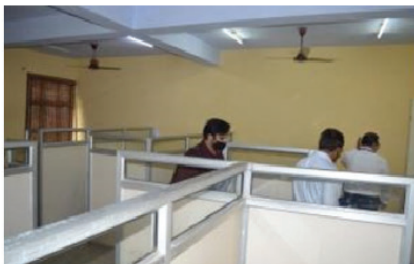

◆ वर्तमान में प्रदेश में 3400 से अधिक स्टार्ट–अप इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ किया गया है।

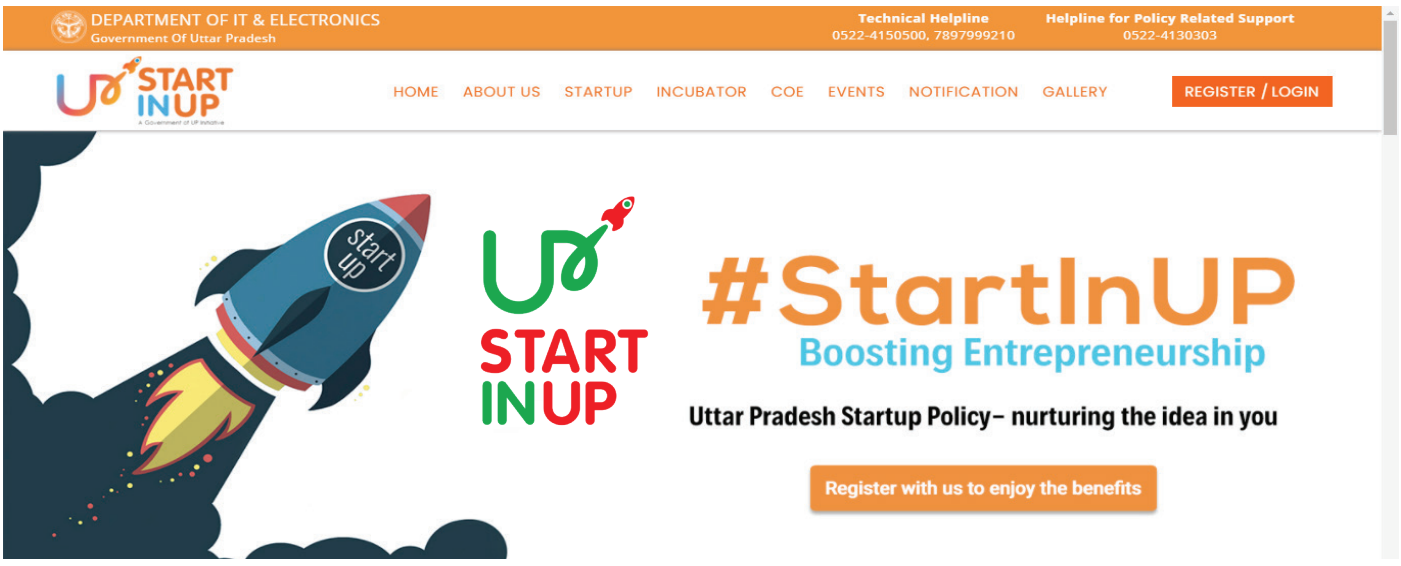

◆ प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट–अप इकाइयों के वित–पोषण के लिए सिडबी के साथ रू. 1,000 करोड़ के स्टार्ट–अप फण्ड तथा 'यूपी एन्जेल नेटवर्क' की स्थापना की गई है।

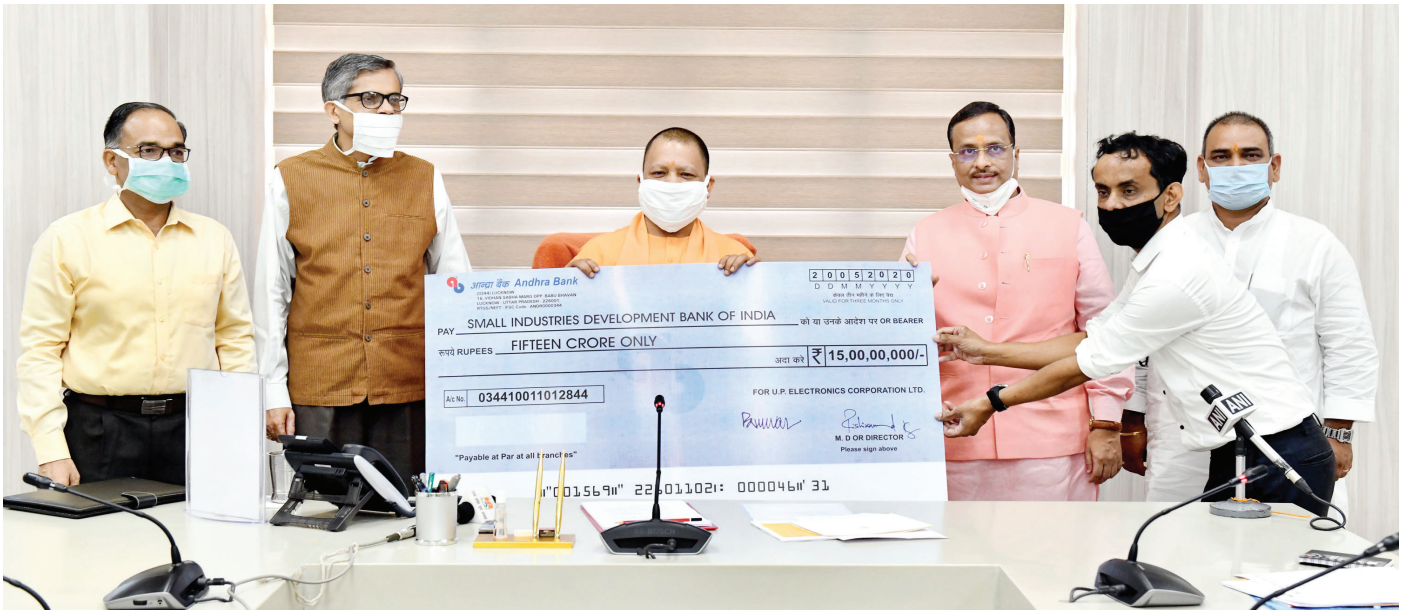

◆ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग रू 200 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना भारत सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया (एस.टी.पी.आई.) के सहयोग से की जा रही है।

@ IT Park, Prayagraj

◆ स्टार्ट–अप नीति के तहत उल्लेखनीय कार्य–प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को स्टेट स्टार्ट–अप रैंकिंग 2018 के अन्तर्गत 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रदेश सरकार के स्टार्ट–अप प्रयासों की सराहनास्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को स्टेट स्टार्ट–अप रैंकिंग 2019 के अन्तर्गत 'इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम' की श्रेणी में रखा गया है तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश तथा स्टार्ट–अप कार्यकलापों के लिए नोडल संस्था के अधिकारियों को भी प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये गये हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

State Startup Ranking 2018

CERTIFICATE OF APPRECIATION

Awarded to

Government of Uttar Pradesh
(Information Technology & Electronics Department)
for being recognized as an

ASPIRING LEADER

in developing an enabling Startup ecosystem in the State.

The State Government has taken several praiseworthy initiatives in establishing:

- Entrepreneurship cells in all districts
- An effective mechanism for awareness and outreach through boot-camps
- A mechanism for seed funding of Startups through sustenance allowance and marketing assistance

The State is also recognized as Leader for:

1. Incubation Hub
2. Regulatory Change

Date: 20th December 2018

Ramesh Abhishek, IAS
Secretary to Government of India
Department of Industrial Policy & Promotion

#startupindia

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

States' Startup Rankings 2019

CERTIFICATE OF APPRECIATION

AWARDED TO

Government of Uttar Pradesh
Information Technology & Electronics Department

FOR BEING RECOGNISED AS AN

Emerging Startup Ecosystem

The Government of Uttar Pradesh has taken several praiseworthy initiatives. Some of them include:

- A Startup Fund which provides access to finance exclusively to UP based startups
- An effective mechanism for awareness and outreach through bootcamps and events
- A mechanism for seed funding of Startups through sustenance allowance and marketing assistance

Date: 11th September, 2020

Dr. Guruprasad Mohapatra
Secretary to Government of India

#startupindia

उत्तर प्रदेश स्टार्ट–अप नीति 2020

◆ प्रदेश सरकार द्वारा 'उ.प्र. स्टार्टअप नीति–2020' के अन्तर्गत प्रदेश में गैर–आईटी क्षेत्रों – यथा कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु प्राविधान किए गए हैं।

◆ नीति के अन्तर्गत प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक इन्क्यूबेटर तथा राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना के अनुकूल ईकोसिस्टम का सृजन की स्थापना का लक्ष्य है। नीति के कार्यान्वयन से प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1,00,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की सम्भावना है।

◆ उ.प्र. स्टार्टअप नीति–2020 के अन्तर्गत राज्य में 3 स्टेट–ऑफ–आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से प्रथम उत्कृष्टता केन्द्र मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया, भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

◆ नीति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित ''राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग'' के अन्तर्गत शीर्ष तीन राज्यों में स्थान ग्रहण करना तथा प्रदेश में 100 इन्क्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इन्क्यूबेटर की स्थापना किया जाना परिलक्षित किया गया है।

◆ राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना के अनुकूल ईकोसिस्टम का सृजन किया जाना भी परिलक्षित है।

◆ इस नीति के अन्तर्गत गठित नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, बॉदा, बीएचयू के अटल इन्नोवेशन सेन्टर, नैस्कॉम 10000 स्टार्टअप वेयर हाउस–नोएडा, जयपुरिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट – लखनऊ, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ, जीएल विश्वविद्यालय– मथुरा तथा कृष्णा इन्जीनियरिंग कालेज –गाजियाबाद में इन्क्यूबेटर स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

◆ इसी कम में नीति के अन्तर्गत एक अन्य उत्कृष्टता का केन्द्र आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में ग्रेटर नॉयडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए आईआईटी कानपुर तथा फिक्की द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सकिय रूप से विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति

प्रस्तावित उ. प्र. डाटा सेन्टर नीति

- इस नीति का उद्देश्य देश मे डाटा सेन्टर उपकरणों (सू0प्रौ0 तथा गैर सू0प्रौ0) के निर्माण के सम्भावित अवसरों की पहचान करके हाल ही में घोषित ''आत्मनिर्भर भारत'' पहल को मजबूत किया जाना है।
- प्रदेश में डाटा सेन्टर पार्क्स तथा डाटा सेन्टर इकाइयों को प्रोत्साहन देकर उनकी स्थापना कराये जाने से वृहद स्तर का निवेश सम्भावित है, अतः प्रदेश सरकार द्वारा एक डाटा सेन्टर नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत राज्य में 250 मेगा वॉट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में रु 20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट किया जाना तथा कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित कराये जाने का लक्ष्य है।

- नीति के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क्स और डाटा सेन्टर इकाइयों को पूँजी उपादान, ब्याज उपादान, भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट तथा ऊर्जा से सम्बन्धित वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त विभिन्न गैर वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रस्तावित हैं।
- बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं।

@ Yotta Data Center Park, Greater Noida

शासकीय विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली

◆ रु. 10 लाख से ऊपर के सभी निविदाओं को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी है।

◆ ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश ई–टेण्डरिंग के क्षेत्र में देश में गत तीन वर्षों से प्रथम स्थान पर है।

◆ अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के मध्य इलेक्ट्रानिक टेण्डरिंग करने वाली प्रदेश सरकारों में से उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए 'बेस्ट परफारमेन्स अवार्ड' से पुरस्कृत किया गया है।

◆ पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा टेण्डरिंग प्रकिया में असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा मई 2017 से शासन के सभी विभागों इत्यादि में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है तथा रु 10 लाख से ऊपर के सभी निविदाओं को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी है।

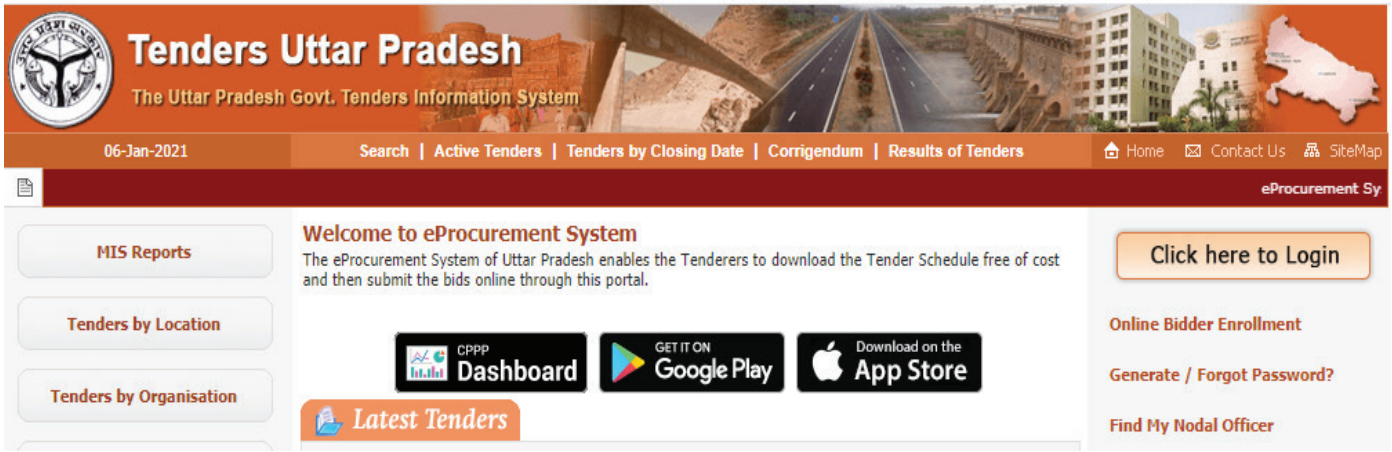

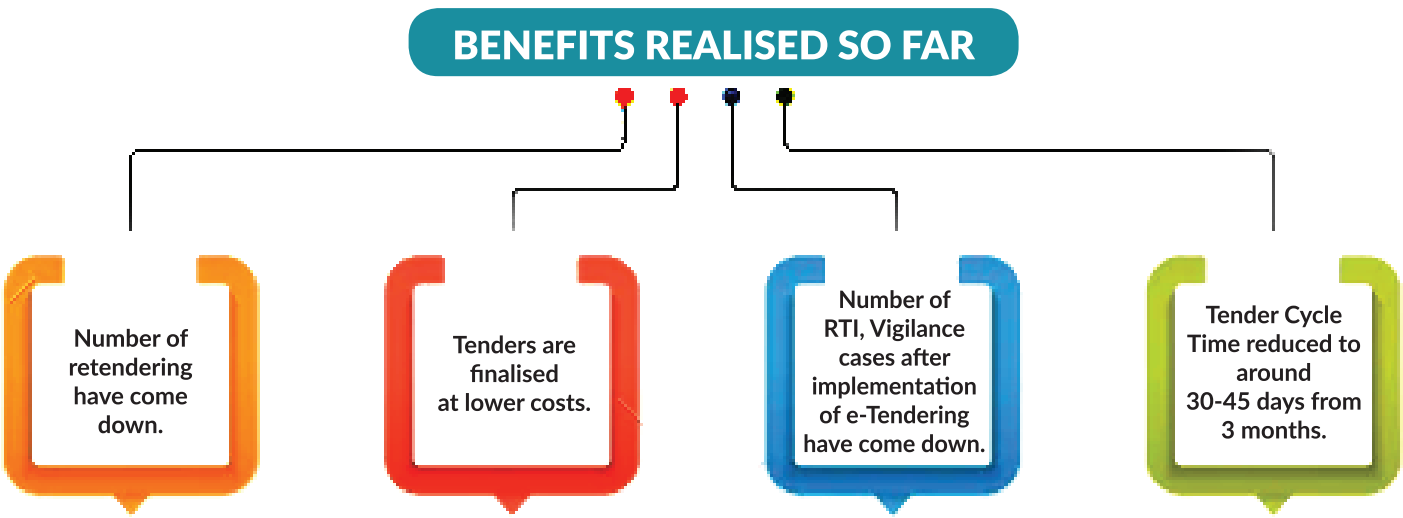

वर्ष	प्रकाशित ई–टेण्डर्स	टेण्डर्स का कुल मूल्य (रू करोड़)	देश में स्थान
2016–2017	15,117	82,529	13वॉ स्थान
2017–2018	1,87,875	1,94,842	प्रथम स्थान
2018–2019	2,52,688	1,77,824	प्रथम स्थान
2019–2020	1,77,203	1,20,834	प्रथम स्थान

◆ वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 की विषम स्थिति में भी प्रदेश में 31 दिसम्बर 2020 तक रु 1.367 लाख करोड़ मूल्य की 1,37,555 निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

◆ एनआईसी के ई–टेण्डर पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की 14,237 संस्थाएं प्रदेश में 24,240 विभागीय यूजर्स तथा 61,873 सप्लायर/वेण्डर्स पंजीकृत हैं।

राइट–ऑफ–वे पॉलिसी की ऑनलाइन व्यवस्था

- भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किया गया है।
- प्रदेश में दूरसंचार नेटवर्क के सुदृढ़ विस्तार हेतु भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख रखाव (ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु) राइट–ऑफ–वे अनुमतियों के लिए आवेदन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।
- आवेदनों के निस्तारण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 60 दिनों के सापेक्ष प्रदेश शासन द्वारा आवेदन की तिथि से 45 (पैंतालिस) दिवस की अवधि निर्धारित की गई है। इस सेवा को निवेश–मित्र पोर्टल से एकीकृत करके जनहित गारण्टी ऐक्ट से जोड़ दिया गया है।

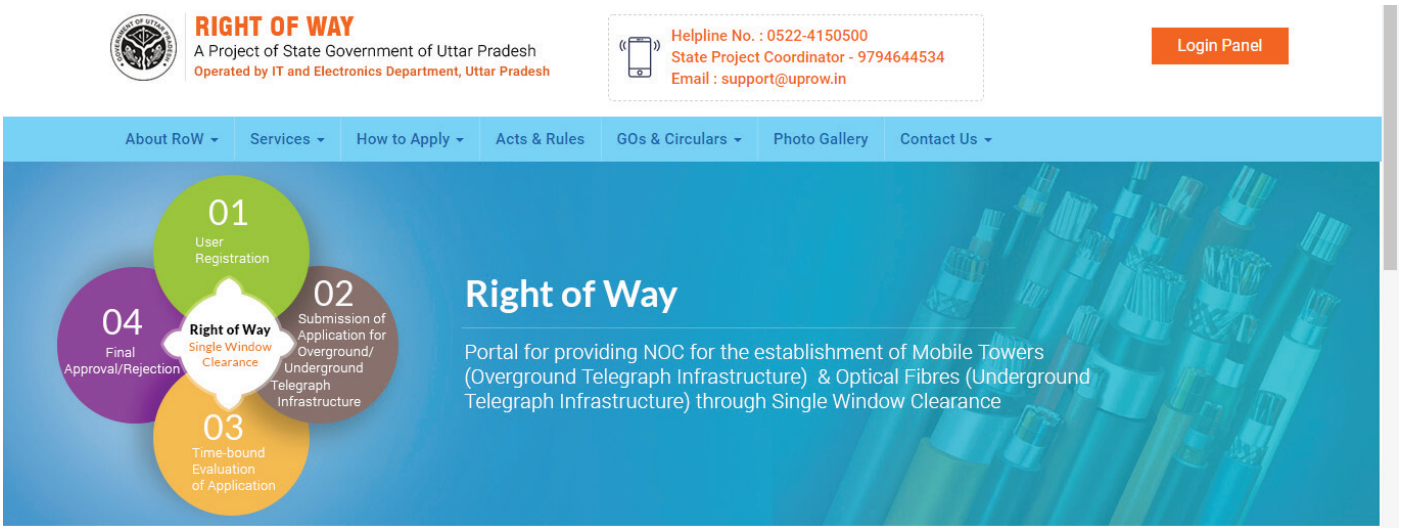

नेशनल ब्रॉडबैण्ड मिशनः भारत नेट

- नेशनल ब्रॉडबैण्ड मिशन, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन नीति–2018 का एक भाग है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक देश के सभी गॉवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है।
- इस कार्य को भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान
National Broadband Mission

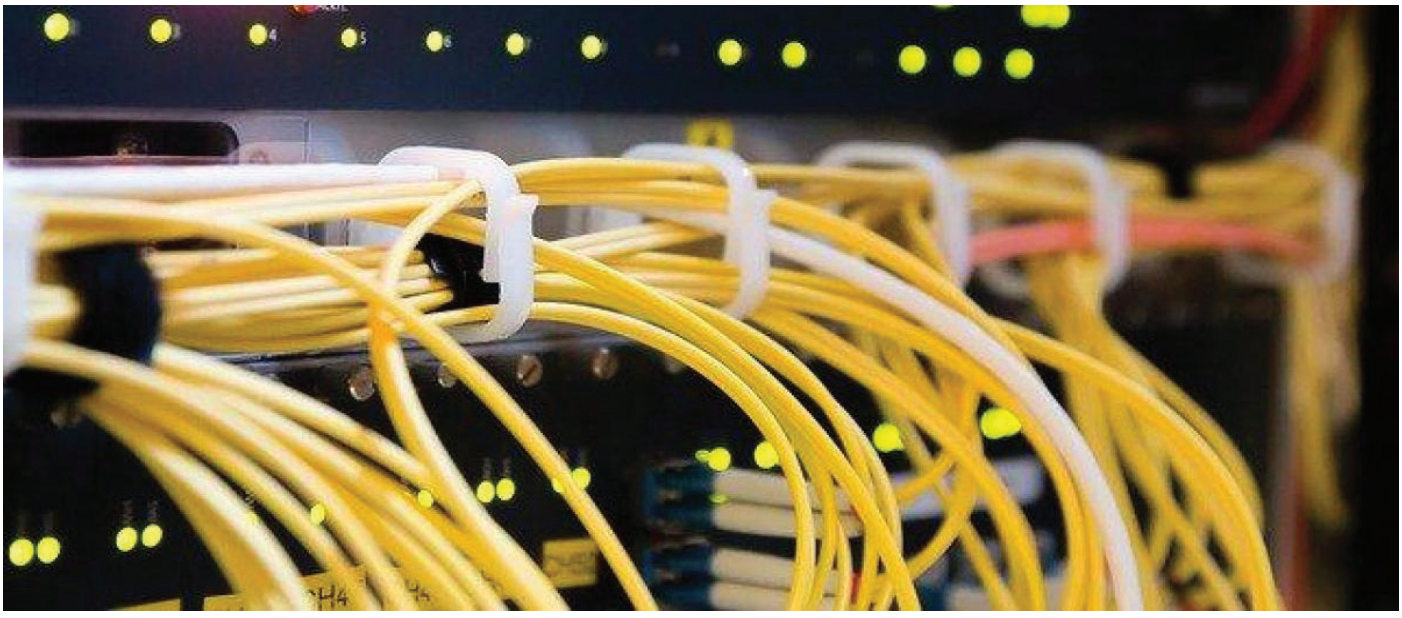

जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी–3.0)/ ई–डिस्ट्रिक्ट योजना

- उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सीएससी–3.0 परियोजना दिनॉक 16 नवम्बर 2020 से प्रभावी हो गई है।
- सी.एस.सी. 3.0 योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदो में 02 – 02 डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स (डी.एस.पी.) का चयन किया जा चुका है।
- प्रत्येक जनपद पर 02 – 02 डीएसपी संस्थाओं के चयन से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिसके कारण आम जनमानस को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- सी.एस.सी. 3.0 परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 जन सेवा केन्द्र एवं शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक 10000 आबादी पर 02 जन सेवा केन्द्र खोले जाएंगे। इस परियोजना अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में 1.5 लाख जन सेवा केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।
- प्रदेश के समस्त जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों के उपयोगार्थ 34 विभागों की 254 शासकीय सेवायें उपलब्ध रहेंगी।
- इस परियोजना में लगभग 4.50 लाख ग्रामीण युवा उद्यमियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा एवं उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- सी.एस.सी. 3.0 परियोजना से समस्त शासकीय सेवायें (आय, जाति, निवास प्रमाण–पत्र इत्यादि) का शुल्क रु 30/– प्रति आवेदन है, जिसमें परिणामस्वरूप जन सेवा केन्द्र संचालकों को पूर्व की तुलना में प्रति आवेदन प्राप्त होने वाले अंश में तीन से चार गुना (अधिकतम रु 15/–) तक वृद्धि हुई है।

यूपी स्वॉन 2.0

- यूपी स्वॉन 2.0 योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपद/तहसील/ब्लॉक मुख्यालयों में 10 एमबीपीएस ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है।
- यह सरकार का डेडीकेटेड एवं सुरक्षित सीयूजी नेटवर्क है, जिसका उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा जन सामान्य को सेवायें प्रदान करने तथा अन्तर्विभागीय संवाद में भी किया जाता है।
- इस परियोजना में नवीनतम एम.पी.एल.एस. टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 885 प्वाइन्ट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) को कनेक्ट किया गया है।
- योजना के पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित है।

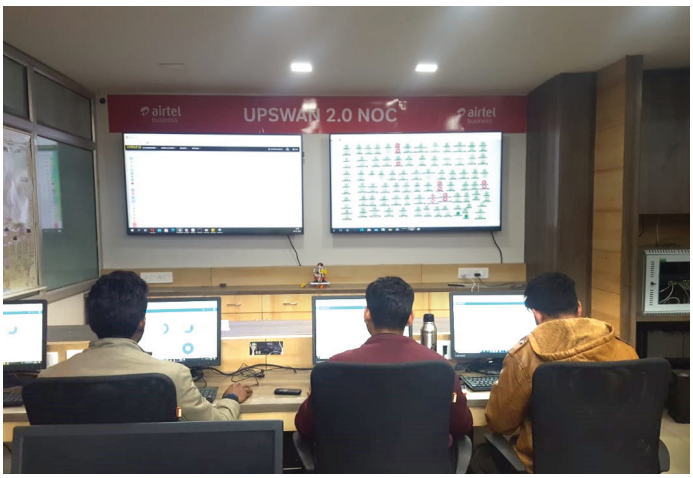

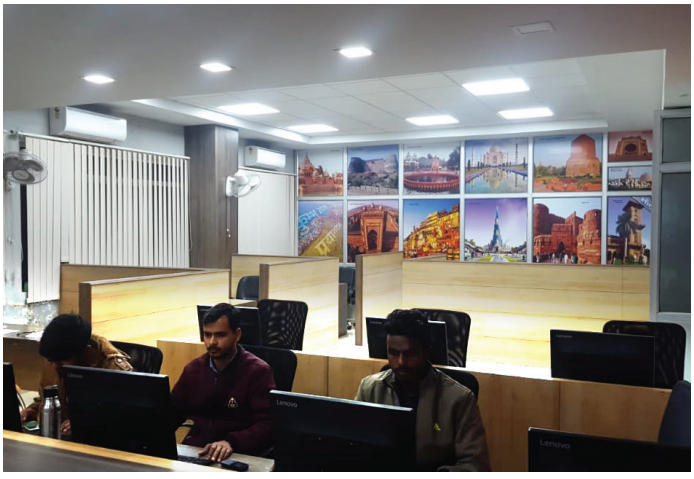

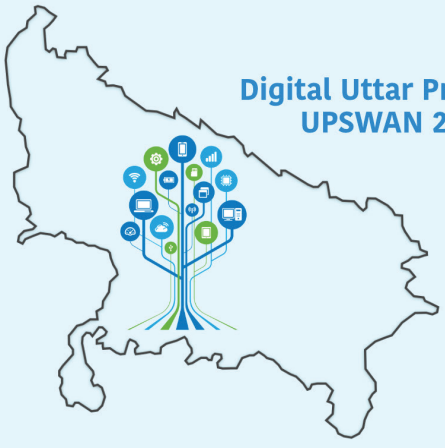

उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर

- राज्य मुख्यालय लखनऊ में आई.एस.ओ 27001 एवं आई.एस.ओ. 20000 प्रमाणित, टियर–2 डाटा सेन्टर की स्थापना पर की गई है।
- स्टेट डाटा सेन्टर में वर्तमान में 155 विभागीय पोर्टल्स अथवा एप्लीकेशन्स होस्टेड हैं। यह डाटा सेन्टर प्रदेश के समस्त विभागों के लिए सम्बन्धित डाटा और एप्लीकेशन्स की होस्टिंग और संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उ.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर 99.98 प्रतिशत अपटाइम के साथ संचालित है।
- यह डाटा सेन्टर प्रदेश के समस्त विभागों के लिए सम्बन्धित डाटा और एप्लीकेशन्स की होस्टिंग और संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उ. प्र. स्टेट डाटा सेन्टर 99.98 प्रतिशत अपटाइम के साथ संचालित है।
- शीघ्र ही स्टेट डाटा सेन्टर का विस्तारीकरण प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) योजना (जनसुनवाई पोर्टल)

◆ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना में 500–सीटर कॉल सेन्टर पर नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण सम्बन्धित विभागों के स्तर से किए जाने की व्यवस्था है।

◆ यह प्रतिदिन 80,000 इनबाउण्ड कॉल्स तथा 55,000 आउटबाउण्ड कॉल्स की क्षमता के साथ संचालित है।

◆ कोविड–19 संकट के दौरान कोविड नियंत्रण कक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्य करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा 23 मार्च 2020 से अब तक 43 लाख से अधिक कॉल्स अटेण्ड की गई।

उत्तर प्रदेश सेन्टर ऑफ जियो–इन्फॉर्मेटिक्स (यूपी सीओजी)

◆ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सेन्टर ऑफ जियो–इन्फॉर्मेटिक्स पर जियो इन्फॉर्मेशन प्रणाली पर आधारित डिसीजन सपोर्ट प्रणाली आरम्भ और विकसित की गई है। इस प्लेटफार्म का उपयोग कर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/निगमों/उपक्रमों द्वारा अपने Assets/डाटा की मैपिंग जी.आई.एस. पर की जा रही है।

◆ इससे शासकीय योजनाओं और नीतियों के ग्राम स्तरीय नियोजन, अनुश्रवण तथा प्रबन्धन में सुगमता हुई है। अद्यतन यूपी सीओजी पोर्टल पर 235 जियो पोर्टल विकसित किये गये हैं।

◆ उत्तर प्रदेश सेन्टर ऑफ जियो–इन्फॉर्मेटिक्स प्लेटफार्म का उपयोग कर विभिन्न विभागों द्वारा अपने से सम्बन्धित विभिन्न Decision Support System (DSS) का सृजन किया जायेगा जिसमें सड़क निर्माण, बाँधों का निर्माण, चिकित्सालय, विद्यालय, कृषि, खेती योग्य भूमि, नलकूप, नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं, व्यवसायिक शिक्षा, दुग्ध विकास, जनसांख्यिकीय विवरण, निवेशक सहायता प्रणाली, एसेट मैपिंग, वन एवं वन्य जीव, गेहूं खरीद इत्यादि सम्मिलित हैं।

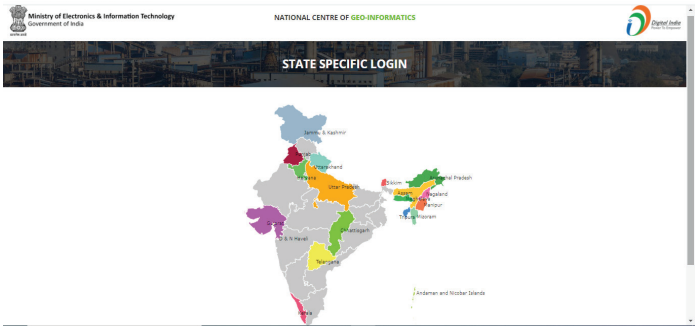

डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रॉंसफर (डीबीटी)

- उ. प्र. स्टेट डाटा सेन्टर पर एक डीबीटी पोर्टल विकसित तथा होस्ट किया गया है। स्टेट डीबीटी पोर्टल पर वर्तमान में प्रदेश सरकार के 27 विभागों की 130 डीबीटी योजनाओं को ऑनबोर्ड किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु. 56,000 करोड़ से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई गई है।
- स्टेट डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल से एकीकृत किया गया है। इसे माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड 'दर्पण' से भी एकीकृत किया गया है।

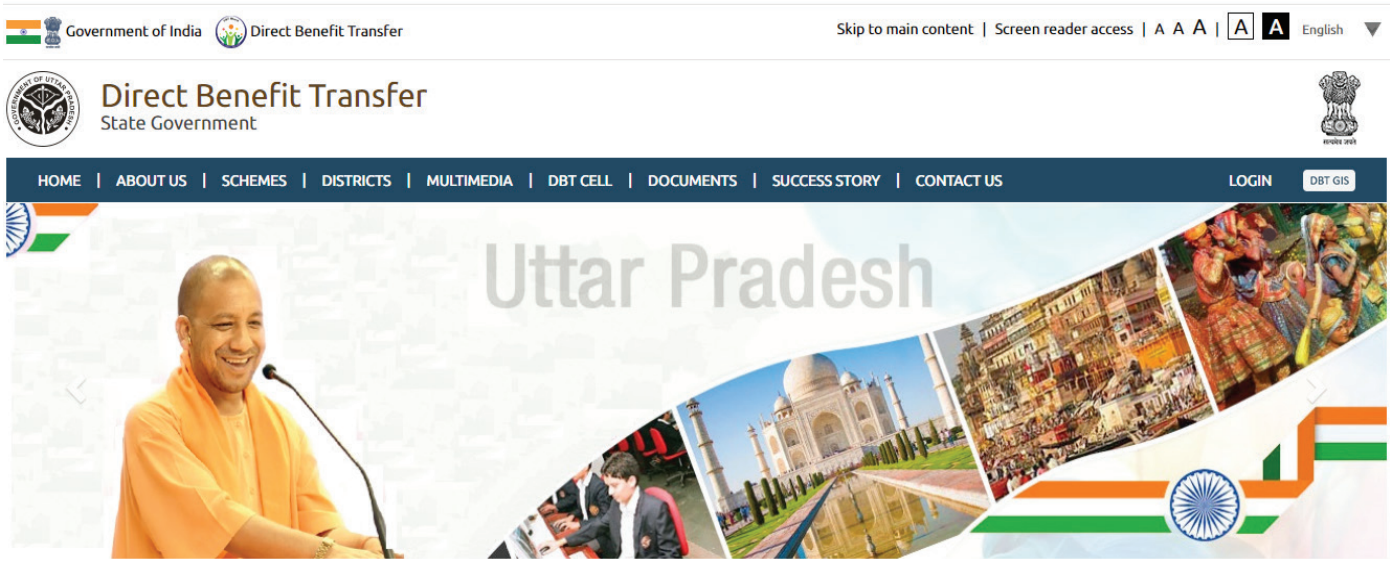

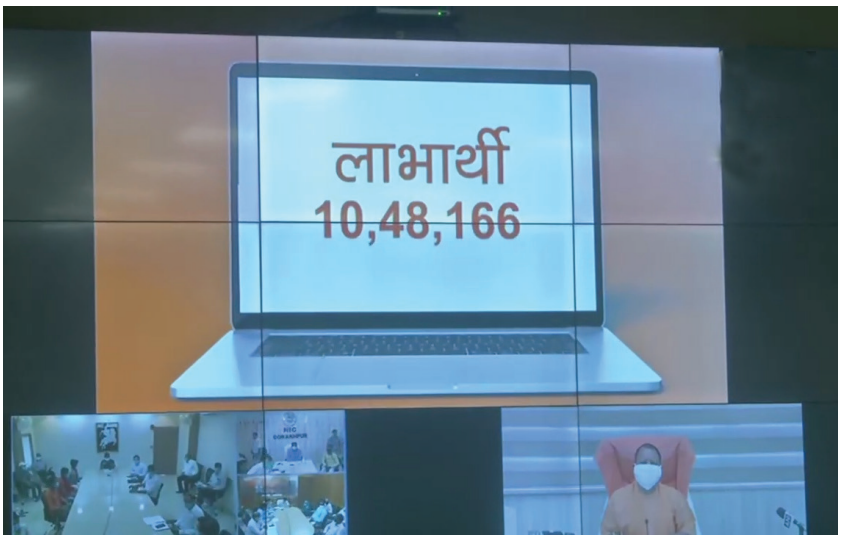

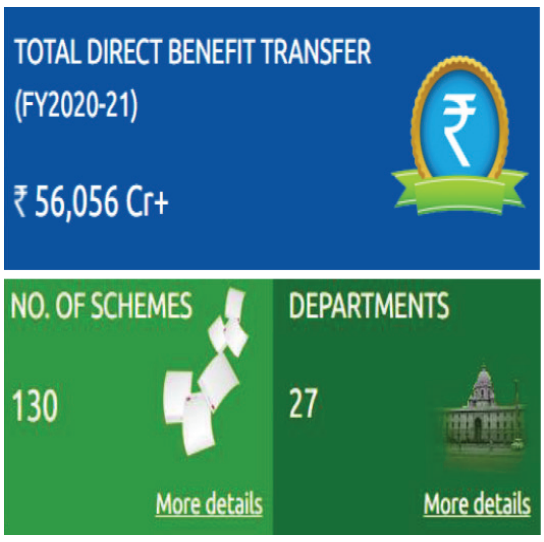

डिजिटल लॉकर/डिजिटल पेमेंट

- इस योजना के अन्तर्गत देश का प्रत्येक नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान–पत्र, पासपोर्ट, जन्म या शादी के प्रमाण–पत्र आदि को इस लॉकर में संरक्षित कर सकता है।
- ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं (महत्वपूर्ण प्रमाण–पत्र यथा आय, जाति, निवास इत्यादि) का डिजिटल लॉकर से इन्टीग्रेशन प्रदेश में किया जा चुका है।
- इस योजनान्तर्गत प्रदेश में अद्यतन 30 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर खोले जा चुके हैं।
- प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आई.टी.आई.), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) द्वारा जारी मार्कषीट एवं प्रमाण–पत्रों को डिजीलॉकर से इन्टीग्रेशन पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश में डिजिटल लेन–देन
को बढ़ावा देने के लिए
100 वें
डिजिधन मेला
का आयोजन

उमंग / UMANG
(Unified Mobile Application for New-Age Governance)

◆ यह एक केन्द्रीयकृत मोबाईल एप है, जिसका उपयोग कर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विविध नागरिक सेवायें एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

◆ प्रदेश में शासकीय सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म से भी उपलब्ध कराये जाने के कार्य की निरंतर समीक्षा राज्य सरकार के साथ–साथ भारत सरकार के स्तर से भी की जा रही है।

◆ प्रथम चरण में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाना है जिसके क्रम में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का इंटीग्रेशन उमंग पोर्टल पर करने की कार्यवाही एन.आई.सी. के माध्यम से प्राथमिकता पर की जा रही है।

◆ प्रदेश में ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही सिटीजन सेन्ट्रिक सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर इन्टीग्रेट किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 के स्तर से शासनादेश दिनॉक 19–04–2018 निर्गत कर दिया गया है।

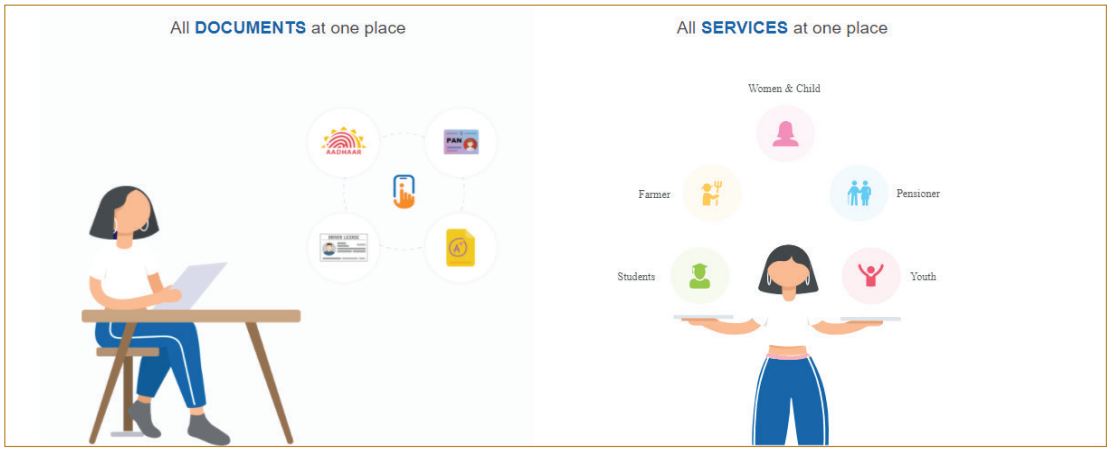

तीन साल में 17 गुना बढ़े स्टार्टअप्स, 22 हजार को मिला रोजगार

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार द्वारा उठाई जा रही नीतियों का असर दिखने लगा है। 2017 के बाद पिछले तीन साल के दौरान प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 17 गुना बढ़कर 3406 हो गई है। इससे प्रदेश में 22 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। 2017 में यूपी में 200 स्टार्टअप काम कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के 73 जिलों में स्थापित इन स्टार्टअप के जरिए 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 12 हजार लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिला है।

10 हजार नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद करेगी सरकार

200 से बढ़कर 3406 हुई संख्या प्रदेश में

स्टार्टअप को और बढ़ावा देने के लिए खुलेंगे 100 इनक्यूबेटर

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए स्टार्टअप्स को नई रफ्तार देने के लिए प्रदेश में जल्द ही 100 नए इनक्यूबेटर खोले जाएंगे। आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर खोलने में मदद करेगा। इसके अलावा बड़े शहरों में एक से अधिक इनक्यूबेटर शुरू किए जाएंगे। मौजूदा समय में 18 इनक्यूबेटर काम कर रहे हैं। इन इनक्यूबेटर के जरिए स्टार्टअप शुरू करने वालों को मैनेजमेंट ट्रेनिंग और अन्य जरूरी सेवाएं प्रदान करके नई स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। इनक्यूबेटर की स्थापना के बाद प्रदेश में करीब 10 हजार नए स्टार्टअप्स स्थापित किए जाएंगे। इससे 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और एक लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

नोएडा टॉप पर

आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में सबसे ज्यादा स्टार्टअप नोएडा में हैं। नोएडा में 1154 स्टार्टअप्स स्थापित किए जा चुके हैं। गाजियाबाद में 533, लखनऊ में 500 और प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वांचल क्षेत्र के जिलों में कुल 1219 स्टार्टअप स्थापित किए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश लौटे पेशेवरों और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टेक्सटाइल और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए स्टार्टअप स्थापित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

कोर्स में शामिल होगा नवाचार और उद्यमिता विकास

विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता विकास के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए स्टार्टअप के जरिए यूपी सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन प्रभावी बनाने के लिए दिए टिप्स

जासं, प्रयागराज : आइटी एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के तहत कार्यरत सेंटर ऑफ ई-गवर्नेंस के माध्यम से गांधी सभागार में सोमवार को ई-गवर्नेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम हेल्पलाइन को और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को जानकारी दी गई। कार्यशाला में सोशल मीडिया, ई-आफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट विषयों पर भी कई विभागों के जिला व मंडल स्तरीय अधिकारियों को टिप्स दिए गए। शुभारंभ करते हुए अपर आयुक्त (प्रथम) भगवान शरण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से डिजिटल इंडिया पर तेजी से काम हो रहा है। यह भारत के त्वरित विकास एवं आमजन की खुशहाली के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों से आह्वान किया कि कार्यशाला में सार्थक रूप से भागीदारी करते हुए इसका प्रयोग शासकीय कार्यों में करें। बताया कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए जनसामान्य की पहुंच सीधे शासन तक हो गई है। हेल्पलाइन नंबर 1076 पर जन शिकायतों को प्राप्त करने एवं उसको त्वरित निस्तारित करने के बारे में भी बताया। इसमें एसडीएम विनीत यादव, दिव्याकांत शुक्ल, मंजू श्रीवास्तव, डॉ. भूपेश द्विवेदी, डॉ. हिंद प्रकाश, अर्जुन सिंह, मेराज खान, शशांक राज, योगेश शुक्ला शामिल रहे।

डरें नहीं, लड़ें // घर में रहें, सुरक्षित रहें

नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2020 के तहत...

5 साल में ₹40,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य, चार लाख को रोजगार

स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में बनेंगे इंक्यूबेटर्स

'हर ग्राम पंचायत में दो जनसेवा केंद्र खुलेंगे'

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

States' Startup Rankings 2019

CERTIFICATE OF COMMENDATION

AWARDED TO

Shri Alok Kumar

Additional Chief Secretary, IT & Electronics,
Government of Uttar Pradesh

His efforts have been instrumental in developing:

- A Startup Fund which provides access to finance to UP based startups
- An effective mechanism for awareness and outreach through bootcamps and events
- A mechanism for seed funding of Startups through sustenance allowance and marketing assistance

Date: 11th September, 2020

Dr. Guruprasad Mohapatra
Secretary to Government of India

#startupindia

Govt to set up IT parks at all divisional headquarters

PNS ■ LUCKNOW

The UP government intends to establish IT parks at all divisional headquarters of the state in collaboration with Software Technology Parks of India (STPI). The objective is to have IT parks in all divisions under IT & Start-up Policy, 2017. Additional Chief Secretary, IT and Electronics, Alok Kumar said on Sunday that it has been proposed to set up an IT park on 3 acres of land in Pilkhani industrial area being developed on 200 acres in Saharanpur, with plug-and-play and other facilities, as per the STPI parameters.

He said that the work of setting up IT parks in Meerut and Agra was almost complete and Gorakhpur and Varanasi IT Parks are expected to be set up by September this year. The state government has provided land free of cost for all above-mentioned IT parks and the process of selecting local information technology and start-up companies for these IT parks is also being done simultaneously.

He said that the transfer deed of Jawaharlal Nehru Commercial Complex of ment of IT Park in Varanasi, while STPI would soon commence construction on the land available in Kanpur (Panki) and process was on for obtaining land of Indian Turpentine and Rosin Company for the IT park project in Bareilly.

It is estimated that IT parks under construction at present would attract an investment of about Rs 200 crore and create 15,000 employment opportunities. Kumar said that STPI centres with plug-and-play facility in Lucknow and Prayagraj were already functional while that in Lucknow had recorded exports to the tune of Rs 230 crore in the year 2019-20 as a result of the state government's investment-friendly policies and improvement in ease of doing business.

It may be noted that 20 IT/start-up companies are operating from Lucknow STPI centre, which has 50 plug-and-play seats with raw furnished work space in about 2000 sq ft whereas, 10 IT or ITeS (information technology enabled services) companies are functional in Prayagraj STPI centre with 50 plug-and-play seats and 5000 sq ft of raw Development Authority (GIDA) land, out of which 3,432 sq ft has been earmarked for plug-and-play facility and 5,568 sq ft is raw furnished work space. It is expected to provide employment to 4,000 people over a period of five years and export revenue is estimated at Rs 5-10 crore per year.

Almost complete, Meerut's IT park has been set up in an area of 2.5 acres with 25,074 sq ft built-up area and 131 plug-and-play seats, along with raw furnished work space in 3,640 sq ft area. An estimated annual export of Rs 6-10 crore and creation of 5,000 employment opportunities is expected in this IT park.

Similarly, the IT park in Agra is being set up in an area of two acres, in which built-up area is 23,000 sq ft with 122 plug-and-play seats and 2,330 sq ft of raw furnished work space. It is expected to generate 5,000 job opportunities over the five years and Rs 6-10 crore worth of exports annually. Moreover, efforts are being made to arrange sites in government buildings, in vacant buildings of engineering or polytechnic institutions, etc as

₹8.8cr to kickstart centre of excellence for mobile tech

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: In a boost for the mobile phone manufacturing industry, the Union ministry of electronics and information technology has released its first instalment of Rs 6.6 crore for the Centre of Excellence project being developed in Noida. The CoE is scheduled to be completed by the end of 2023.

Additional chief secretary, IT and electronics, Alok Kumar said that the state government has also consented to release Rs 2.2 crore as its share towards the project, being developed under the state's Electronic Manufacturing Policy, so that the first phase of development can start.

The CoE will work towards transfer of technology and provide product testing support. "Infrastructure for testing and other requirements with a fully functional testing lab which will be used by the Bureau of Indian Standards (BIS) will be developed at the centre. It will be equipped with a tool room and component library," Kumar said.

He added that once established, five products, including chargers, power banks and wireless power banks, LED and speakers based on lithium-ion cells will be developed and tested during the first year. Four products will be developed during the second year, including battery monitoring system for electric vehicles, solar plants and solar system battery pack, whereas, GPS navigation system, UPS system, sountimeter and ticket vending machines are proposed to be developed during the third year.

PROJECT TO BE SET UP IN NOIDA

"Other than services to the electronics industry, facilities for skill development in electronic system design and development will also be provided at the CoE. It will also provide standardization and testing support for in-country and global needs," Kumar added.

The project is being implemented by the Centre for Development of Advanced Computing, Noida in collaboration with the Indian Cellular and Electronics Association (ICEA) at an estimated cost of Rs 16.76 crore. Of this, the Centre's share is Rs 8.55 crore, while the UP government and ICEA will contribute Rs 2.85 crore and Rs 5.36 crore respectively.

"The project implementation period had been fixed at 36 months from December 30, 2020, and therefore, the CoE is well on course to be completed by the last week of December, 2023. The objectives of the CoE are aimed at design and development of products related to the power bank industry, mobile handset accessories and electronics applications," the ACS said.

आईटी पार्कों में निवेश से मिलेगा 15,000 को रोजगार

अवसर

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

02 अरब रुपये का निवेश होगा

10 करोड़ का निर्यात राजस्व अनुमानित

सहारनपुर में 200 एकड़ में विकसित किए जा रहे पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र में तीन एकड़ में आईटी पार्क बनाया जाएगा। मेरठ एवं आगरा में आईटी पार्कों का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर एवं वाराणसी में इस साल सितम्बर तक आईटी पार्क बन जाएंगे। निर्माणाधीन आईटी पार्कों में लगभग रु 200 करोड़ के निवेश एवं 15,000 रोजगार के अवसर बनेंगे।

औद्योगिक विकास विभाग व आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मण्डलों में आईटी पार्कों अथवा साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कों की स्थापना होगी। सभी आईटी पार्कों के लिए भूमि की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है और इन आईटी पार्कों के लिए स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप कंपनियों के चयन की प्रक्रिया भी साथ-साथ कराई जा रही है। वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जवाहर लाल नेहरू कामर्शियल काम्पलेक्स में आईटी पार्क की स्थापना के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पक्ष में इस निर्मित भवन का हस्तान्तरण विलेख प्रक्रियाधीन है।

लखनऊ के एसटीपीआई केंद्र से 230 करोड़ का निर्यात

आलोक कुमार ने कहा कि वर्ष 2019-20 में लखनऊ के एसटीपीआई केंद्र से रु. 230 करोड़ का निर्यात हुआ है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की 3.58 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क का विकास किया गया है। इसमें पांच वर्ष की अवधि में 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और प्रतिवर्ष 5-10 करोड़ रुपये का निर्यात राजस्व अनुमानित है। मेरठ के आईटी पार्क में पांच वर्ष की अवधि में 5,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और प्रतिवर्ष 6-10 करोड़ रुपये का निर्यात राजस्व अनुमानित है। आगरा में आईटी पार्क से पांच वर्ष में 5,000 रोजगार के अवसरों और प्रतिवर्ष 6-10 करोड़ रु.का निर्यात सम्भावित है।

जनपद की 630 ग्राम पंचायतों में फ्री नेट की सुविधा

अलापुर | हिन्दुस्तान संवाद

जनपद की 630 ग्राम पंचायतों में बने स्कूल, सीएससी सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, राशन डीलर की दुकान, पंचायत घर, उपकेंद्र आदि के लिए एक मई से फ्री इंटरनेट की सुविधा को मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए तय किए स्थान पर हॉट स्पॉट बॉक्स लगाए जा रहे हैं। नेट चलाने के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी दिया जा रहा है।

सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश की एक लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टीकल फाइबर द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ सीएससी ई गवर्नेंस से जोड़ दी हैं। इसका लाभ 630 ग्राम पंचायतों के स्कूलों, सीएससी सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, राशन डीलर की दुकान, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, उपकेंद्र समेत अन्य सरकारी विभागों से जुड़े कार्यालयों के लिए शुरू हो गया है। सीएससी जिला प्रबंधक शोभित माहेश्वरी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के सहयोग से गांवों में सरकारी स्कूलों में एक जून से इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई है।

कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के सहयोग से गांव में फ्री नेट की सुविधा मिलने के बाद लैपटॉप चलाते ग्रामीण। • हिन्दुस्तान

खुशखबरी, आपको मोहल्ले में मिलेगी 252 सर्विसेज

ई-डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के जरिए सिटी व रूरल एरिया में खोले जाएंगे डीएसपी

gorakhpur@inext.co.in

GORAKHPUR (24 Dec): आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर ट्रेन का टिकट लेना हो. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मोहल्ले में ही डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) 252 सर्विसेज आसानी से दे सकेंगे. यही नहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे. इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है. गोरखपुराइट्स को एक जगह बैठे-बैठे सारी सुविधाएं मिल सके. इसके लिए डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने ई-डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को टेक्नीकली स्ट्रांग कर दिया है. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज को जिम्मेदारी सौंपी है. ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) को बैठाने की प्लानिंग कर दी गई है. सिटी के 70 वार्ड के एक-एक वार्ड में दो-दो डीएसपी बैठेंगे. वहीं, गोरखपुर जिले के 1352 गांव में भी दो अलग-अलग कंपनी के डीएसपी 252 सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे. गोरखपुर जिले में 3200 लोगों को डीएसपी बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे.

थंब इंप्रेशन के जरिए पा सकेंगे पैसा

ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज ने बताया कि डीएसपी के तैनाती के लिए दो कंपनी सहज व बीएलएस से करार है. इन्हें ई-टेंडर के माध्यम से चुना गया है. वे बताते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट डॉट एनआईसी डॉट इन पर लॉगिन करते हुए अप्लाई कर ज्यादा जानकारी डीएसपी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि आधार इनेबल पेइंग सिस्टम (एईपीएस) के जरिए कंज्यूमर अपने आधार कार्ड नंबर दिखाकर थंब इंप्रेशन के जरिए पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं.

> सिटी से लेकर रूरल एरिया में पब्लिक की सुविधा के लिए डीएसपी तैनात किए जा रहे हैं. इसके जरिए लोगों को आसानी से 252 सुविधा का लाभ ले सकेंगे. जरूरी काम के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
>
> **के विजयेंद्र पांडियन,** डीएम

इनकी मिलेगी सुविधाएं

- आय, जाति, निवास, परिवार रजिस्टर नकल, मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र के लिए तहसील ब्लॉक पर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.
- महीनों दौड़-भाग के करने के बाद भी लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते है.
- सिटी में दस हजार की आबादी पर दो-दो डीएसपी बैठाने की है प्लानिंग
- बेरोजगारों को मिल सकेगा रोजगार

फैक्ट फीगर

- जिले भर में रखे जाएंगे 3200 डीएसपी
- 1352 गांव में होगी तैनाती
- सिटी के 70 वार्ड में रखे जाएंगे डीएसपी

डीएसपी सेंटर पर पब्लिक को ट्रेन का टिकट, डीएल समेत एईपीएस की सुविधा का मिलेगा लाभ

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

States' Startup Rankings 2019

CERTIFICATE OF COMMENDATION

AWARDED TO

Shri Rishirendra Kumar

Managing Director, Startup Nodal Agency UPLC,
Government of Uttar Pradesh

He has led several initiatives to support startups in the state across sectors and regions. Some of his contributions include:

- Leading many startups to evolve throughout the startup cycle within the state as well as from other states coming to Uttar Pradesh for business growth
- Supporting the state machinery to form an effective state policy for startups and incubators

Date: 11th September, 2020

Dr. Guruprasad Mohapatra
Secretary to Government of India

#startupindia

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए अब यूपी में नई नीति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अब तक सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र तक सिमटे इलेक्ट्रॉनिक्स हब को सरकार पूरे प्रदेश में विस्तार देना चाहती है। इसके लिए वर्ष 2017 की पुरानी नीति को बदलते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 मंजूर की गई है। इस नीति में निवेशकों को पूरे प्रदेश में कहीं भी उद्योग लगाने पर छूट दी जाएगी। वहीं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में उद्योग लगाने पर विशेष छूट की भी व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार बनते ही उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 लागू की गई थी। सरकार का दावा है कि यह सफल हुई और निर्धारित लक्ष्य तीन वर्ष में पूरे कर लिए गए। इस नीति का लाभ सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में ही दिया जा रहा था। अब नई नीति पूरे प्रदेश को शामिल करते हुए बनाई गई है, जिसे मंगलवार को सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी।

इससे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों को पीपीपी मोड पर प्लग एंड प्ले मॉडल पर किराए की सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस नीति के माध्यम से अगले पांच वर्ष में चालीस हजार करोड़ रुपये के निवेश और चार लाख

कैबिनेट के फैसले

सिर्फ नोएडा, ग्रेनो और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण नहीं, पूरे प्रदेश में विस्तार, पूर्वांचल व बुंदेलखंड में मिलेगी विशेष छूट

नीति के प्रमुख बिंदु

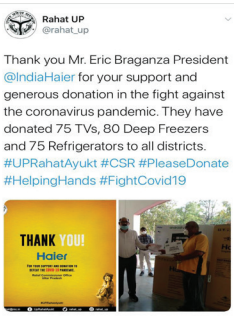

- निवेशक 15 फीसद पूंजी उपादान और एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश पर दस फीसद अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी के पात्र होंगे
- अधिसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर पांच फीसद प्रतिवर्ष ब्याज सब्सिडी अनुमन्य होगी
- बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में निवेशकों को प्रचलित सेक्टर दरों पर पचास फीसद भूमि सब्सिडी दी जाएगी
- वैश्विक निवेशकों को लक्षित करने के लिए स्थिर पूंजी निवेश के चालीस फीसद तक पुनर्निमित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति होगी
- फैब इकाइयों के लिए भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूंजी, सहभागिता, वित्तीय प्रोत्साहन और गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित विशेष पैकेज पर विचार किया जाएगा।

Rahat UP @rahat_up

Thank you Mr. Eric Braganza President @IndiaHaier for your support and generous donation in the fight against the coronavirus pandemic. They have donated 75 TVs, 80 Deep Freezers and 75 Refrigerators to all districts. #UPRahatAyukt #CSR #PleaseDonate #HelpingHands #FightCovid19

प्रदेश में खुलेंगी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में स्थापित मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को भी शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रमुख सचिव आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के साथ-साथ मोबाइल की असेसरीज यूनिट्स (मोबाइल निर्माण से संबंधित उपकरण बनाने वाली यूनिट) को भी खोला जाएगा। इन यूनिट्स को जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स की तरफ से लगातार खोलने की मांग की जा रही थी।

प्रमुख सचिव, आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने जारी किया आदेश

मिलता है दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार

इन यूनिट्स को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। इन यूनिटों के खुल जाने से बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उससे दो लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है।

Bhanu Pratap Singh @bhanu_cashcry

It was a great opportunity to meet up with IAS Shri Rishirendra Kumar @iasRishi Sir (Special Secretary, IT and Electronics) Apart from his insights on UP's new start-up policy in 2020, we discussed on how to further improve the Start-Up Ecosystem in UP. #upstartuppolicy2020

देश में कहीं भी बनें मोबाइल पर चलेंगे नोएडा की बैटरी से ही

- **केंद्र ने दिया तोहफा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस में लिथियम आयन बैटरी पर होगा रिसर्च और किया जाएगा निर्माण**

रिंकू यादव। नोएडा

प्रतीकात्मक फोटो

नोएडा शहर के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अब मोबाइल फोन देश के किसी भी हिस्से में बने लेकिन उनके लिए बैटरी नोएडा में ही बनाई जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नोएडा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कर रही हैं, जो अगले 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा।

इस सेंटर में मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी लिथियम आयन बैटरीज पर रिसर्च और निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए अपने हिस्से की जरूरी धनराशि जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को उन्नत तकनीकी सहायता का लाभ प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति के तहत नोएडा में उत्कृष्टता केन्द्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना त्वरित गति से की जा रही है। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा में लिथियम आयन सेल आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 659,66 लाख रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के पहले चरण को प्रारम्भ करने के लिए 219,90 लाख रुपये के अपने अंशदान के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन आईसीईए के सहयोग से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी-डैक नोएडा द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली उत्कृष्टता केन्द्र परियोजना की अनुमानित लागत 1675,89 लाख रुपये है, जिसमें से 854,90 लाख रुपये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योगदान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और आईसीईए द्वारा क्रमशः 284,99 लाख रुपये तथा 536 लाख रुपये का योगदान किया जाएगा।

आलोक कुमार ने कहा कि परियोजना कार्यान्वयन की अवधि बीते 30 दिसंबर से 36 महीनों के लिए निर्धारित की गई है। उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना का कार्य दिसंबर 2023 के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण होने की संभावना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मकसद पावर बैंक उद्योग, मोबाइल हैंडसेट के पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन्स से संबंधित उत्पादों को डिजाइन और उनका विकास करना है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता केन्द्र प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीक्षण सुविधा के हस्तांतरण के लिए उद्योगों से संपर्क के साथ ही स्वावलम्बी व्यापारिक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस केन्द्र में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा उपयोग करने योग्य पूर्ण रूप से क्रियाशील परीक्षण प्रयोगशाला के साथ परीक्षण और अन्य सम्बंधित आवश्यकताओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

STPI @stpiindia · 20s

Replying to @stpiindia

"Government of UP will support this CoE on many fronts & our CM is very keen on medical electronics," underlined Sh. Rishirendra Kumar, Special Secretary, IT & Electronics, Govt. of UP. #STPIINDIA #STPICoEs #STPIMedTech #STPIPulse @iasRishi

Watch live: bit.ly/stpipulse-medt...

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

States' Startup Rankings 2019

CERTIFICATE OF COMMENDATION

AWARDED TO

Shri Praveen Kumar

Deputy General Manager, UP Electronics Corporation,
Government of Uttar Pradesh

He has been supporting events that are organized to promote the startup ecosystem in the State. He has been instrumental in:

- Driving and managing the approval process of incubator and startups
- Preparation and signing of MoU with SIDBI as for Fund of Funds for UP Startups manager
- Launched a helpline and website for startups to bring all the stakeholders of the ecosystem on one platform

Date: 11th September, 2020

Dr. Guruprasad Mohapatra
Secretary to Government of India

#startupindia

नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी मिली

नई नीति से चार लाख को मिलेगा रोजगार

कैबिनेट फैसले

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अगले 5 सालों में 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी।

इससे पहले 2017 में नीति लाई गई थी । पुरानी नीति नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में लागू थी। नई नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी। वहीं बुंदेलखण्ड व पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त सहूलियतें भी दी जाएंगी। यह नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्षो के लिए होगी।

नई नीति के तहत ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर व ईएसडीएम पार्क की एसपीवी व एकल ईएसडीएम इकाइयों को मध्यांचल या पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से खरीदी जाने वाली जमीन पर सर्किल रेट से 25 % छूट मिलेगी। बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र में 50% छूट दी जाएगी।

खास बातें

- निवेश पर 15 फीसदी की छूट और एक हजार करोड़ से अधिक निवेश पर 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट
- बैंकों, वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज से छूट
- पूंजी निवेश के 40 फीसदी तक के पुराने उपकरण या मशीनें लगाई जा सकेंगी।

UP govt sets aside ₹150 cr to encourage start-ups

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW: The state government will soon start disbursing funds to Uttar Pradesh-based start-ups from a corpus of Rs 150 crore it has created to encourage new ventures in the state as part of its new start-up policy.

The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the fund manager of this start-up fund.

In pursuance of the state's new start-up policy, the government has also decided to set up 100 incubators across UP with at least one in each of the 75 districts. The biggest incubator will come up in the state capital.

"A corpus fund of Rs 150 crore has also been set up by the state government with the help of Abdul Kalam Technical University (AKTU) to fund start-ups at the stage of ideation, patent registration and participation in domestic and international events," said the state government in a press release on Friday.

"The UP start-up fund has garnered interest from leading venture funds/alternative investment funds," added release.

Several academic institutions have shown interest in setting up incubators in their institutions. Among them is Banaras Hindu University, Varanasi.

The state government has also released Rs 41 lakh to the start-up nodal agency to be disbursed to start-ups and incubators whose proposals were already approved by the government's policy implementation committee.

The money will be disbursed to start-ups in the form of sustenance allowance at idea stage, seed capital assistance at commercialisation stage and capital grant to incubators for strengthening IT infrastructure within their premises to be utilized by start-ups and other stakeholders. In the new startup policy, chief minister Yogi Adityanath's concern for regional imbalance in the state, especially Bundelkhand and Purvanchal regions, has also been addressed by offering additional incentives for start-ups and incubators operating from these regions.

This will help in democratising the startup ecosystem across the state, which so far was dominated by Tier-1 cities like Noida.

The policy also focuses on divyangjan, women and transgenders by offering additional incentives and creating employment opportunities for them.

INVESTMENT FUNDS EXPRESS INTEREST

- SIDBI has so far received four applications from leading alternative investment funds in the country for investment of Rs 285 crore to create an initial corpus.
- Decision on these applications will soon be taken by SIDBI and start-up nodal agency in its first venture capital investment committee (VCIC) meeting later this month.

NODAL AGENCY ESTABLISHED

- A nodal agency under the department of IT and electronics has been established for effective implementation of the UP start-up policy. This agency will work closely with incubators/accelerators for evaluation and recognition of start-ups to assess their eligibility for incentives provided in the policy.
- The agency will be the first point of contact for start-ups to engage with the government. It will report directly to the policy implementation unit (PIU) headed by principal secretary, department of IT & electronics.

संपर्क सूत्र:
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
(नीति कार्यान्वयन इकाई / नोडल एजेन्सी)

पता: 10, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001
दूरभाष: 0522 - 4130303, 2286808, 2286809
वेबसाइट: www.uplc.in, ई-मेल: uplclko@gmail.com

नीतियों / योजनाओं से सम्बन्धित सूचना हेतु:
ई-मेल: missiondirectorate@upempolicy.in/ info@itpolicyup.gov.in
वेबसाइट: www.upempolicy.in / startinup.up.gov.in/ itpolicyup.gov.in

(January, 2021)